

प्रतापगढ़ संदेश

अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श बनाएं ग्राम प्रधान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम प्रधानों को दिया गया प्रशिक्षण

अखंड भारत संदेश

कर्तव्य गुलाब सिंह, प्रतापगढ़। ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण के प्रथम दिवस बिहार लॉक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

नवनीर्वाचित ग्राम प्रधानों को पंचायती राज व्यवस्था, प्रधान के कार्य एवं दायित्व और ग्राम स्तरीय समितियां, ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ ही केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग और बैठक वार्ता कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को मिलें वाले पुरस्कारों आदि की जानकारी शासन द्वारा नामित मुख्य



प्रशिक्षक एवं पर्यावरण सेना प्रमुख अजय कांतिकारी और नितेश श्रीवास्तव द्वारा दी गई।

आज प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण सेना प्रमुख एवं मुख्य प्रशिक्षक

पंचायती राज विभाग अजय कांतिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों को पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम

पंचायत विकास योजना निर्माण के बताया। नितेश श्रीवास्तव ने प्रधानों को पंचायत समितियों के बारे में जानकारी दी। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सीमनाथ नायर ने सभी प्रधानों को प्रशिक्षण में दिलीपपुर की टीम को 59-49 के अंतर से पराजित कर चौंपनशिप पर कहा किया।

इसके पूर्व आयोजक शिक्षक नेता राजीव सिंह, लेखापाल अभियंक सिंह रामू ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फाइनल मुकाबले में सहभागिता की शुभारम्भ किया। समाजसेवी अध्यक्ष सोनी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए ग्राम प्रधानों से अपने ग्राम पंचायत को टीमी मुक्त बनाने हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर धर्मराज पर्ल, निशा, धीरेन्द्र प्रताप, शीला देवी, आरती देवी, राम कैलाश और अमर नाथ मिश्र सहित कई लोग मौजूद रहे।

जिला कबड्डी एसोसिएशन के तत्त्वावधान में हुई प्रतियोगिता



18 टीमों ने हिस्सा लिया। लालमणि सिंह, लालौजी तिवारी, मो. इरफान, मो. असिफ निर्णयिक वर्मा, हरिकेश, हरिलाल आदि मौजूद रहे। अंत में संयोजक रवि प्रकाश सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह, अजय कुमार सिंह, आदिव्य शुक्ल, शोभनाथ यादव, राम सजोवन वर्मा, हरिकेश, हरिलाल आदि मौजूद रहे। अंत में संयोजक रवि प्रकाश सिंह ने किया। इंटर कालेज, करागुलाब सिंह, संचालन डा. धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने किया। माध्यमिक शिक्षक सदृश

अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, वांछित को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अखंड भारत संदेश

पट्टी, प्रतापगढ़। मुख्यिकारी की सूचना पर पट्टी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, पुलिस ने भरोसेन नहर पुल वार को एक तमचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पट्टी कोतवाल गणेश प्रसाद सिंह अभियंक सिंह राहुल यादव विकेश मिश्र बृहदीवार को मुख्यिकारी ने सूचना दिया कि एक युवक अवैध तमचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस वहां पहुंची तो आयोपी युवक वहां से सकपका कर भागने लगा पुलिस ने उसे दौड़ाकर पड़ा और तलाशी तो तो उसके पास से 12 बोर का एक तमचा व एक जिंदा

कारतूस मिला। कर्ता करने पर उसने अपना नाम आस्कर सिंह पुरुष हारियाली सिंह निवासी कोमाही वारपाल को गिरफ्तार कर आस्मिन एकत्र के पास एक युवक को एक अवैध तमचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पट्टी कोतवाल गणेश प्रसाद सिंह अभियंक सिंह राहुल यादव विकेश मिश्र बृहदीवार को मुख्यिकारी ने सूचना दिया कि एक युवक अवैध तमचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस वहां पहुंची तो आयोपी युवक वहां से सकपका कर भागने लगा पुलिस ने उसे दौड़ाकर पड़ा और तलाशी तो तो उसके पास से 12 बोर का एक तमचा व एक जिंदा

विधायक और जिलाध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियों का किया बखान

कहा-विकास के मुद्दे पर फिर बनेगी भाजपा की सरकार

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सरकार की उपलब्धियों का ब्लॉक जनता तक पहुंचाने के लिये एक-एक विधान सभा क्षेत्र की उपलब्धियां पत्रकारों को बता रही हैं। युवावार को सदर विधायक राजकुमार पाल ने सदर विधायक राजकुमार जोगांव के आसपुर देवसरा के भनड़ीपुर गांव के पास से मुख्यिकारी का सूचना पर गिरफ्तार किया गया।



नगरीय सीमा में लागं वारे जाम से लोगों को छुकारा दिलाने हेतु प्रात विधायक सभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का ब्लॉक दिया। सदर विधायक राजकुमार जोगांव पाल ने पीड़िलाई डाक बगल पर एक प्रेसवार्ता कर विधान सभा सदर में

को चिकित्सा सम्बन्धी सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। उदय जिलाध्यक्ष भाजपा हिराओम मिश्र ने पीड़िलाई डाक बांले पर प्रेसवार्ता कर विधान सभा विधायक सभा में सरकार के द्वारा कार्यों को गिनाया। श्री मिश्र ने बताया

कि विधान सभा विधायक सभा में एक जनपद एक उत्तर प्रशिक्षण टूलिंग योजनातर्फ 200 लोगों को प्रशिक्षण एवं टूलिंग दिया गया तो ही प्रशिक्षणमित्री रोजगार सजून कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 ज्ञान लागं जिसमें 300 लोगों को रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री माटिकला रोजगार योजना के अन्तर्गत 27 ज्ञान लागं योजनाएं दी गयी। कार्यक्रम के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक चाक का विरपण किया गया और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनातर्फ 27 ज्ञान लागं योजनाएं दी गयी। उदय जिलाध्यक्ष भाजपा हिराओम मिश्र ने पीड़िलाई डाक बांले पर प्रेसवार्ता कर विधान सभा विधायक सभा में सरकार के द्वारा कार्यों को गिनाया। श्री मिश्र ने बताया कि विधान सभा के लाभगत 238 मजरूरों में नियुक्त नियमित की प्रक्रिया प्रारम्भ है तो वहां रूपये 2 अरब 40 करोड़ 65 लाख की लागत से एन020-330 प्रयागराज-अयोध्या मार्ग पर

बकुलाही नदी पुनरोद्धार से जन जन में खुशी

बकुलाही पुत्रों संग समाज शेखर ने किया स्नान

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। बकुलाही नदी पुनरोद्धार वें नतीजे से भयहरणनाथ थाम के जन जीवन में खुशी हो खुशी है। वहां नदी की प्राचीन 21.4 किलो मीटर जल धारा में नदी में एक लॉन्डर जल प्रवाहित हो रहा है जो आपास पास सभी श्रेष्ठों का पेट भर कर जल से संतुष्ट कर दिया। आज बकुलाही पुनरोद्धार अभियान के साथ यजक असाज सांखर ने प्राचीन धारा का व्यापक अप्रयोग करके नदी क्षेत्र का जायजा लिया।

संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर ने भयहरणनाथ थाम के जन जीवन में खुशी हो खुशी है। इसके पास एक लॉन्डर जल प्रवाहित हो रहा है जो आपास पास सभी श्रेष्ठों का पेट भर कर जल से संतुष्ट कर दिया। आज बकुलाही पुनरोद्धार अभियान के साथ यजक असाज सांखर ने प्राचीन धारा का व्यापक अप्रयोग करके नदी क्षेत्र का जायजा लिया।



पेटल को जिलाधिकारी विधायक के नाम प्रस्ताव बनाकर देने का आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। जिसके पास के युवा ग्राम में ग्रामीणों के पुरुषों को जिलाधिकारी विधायक की तरफ से सांस्कृतिक प्रस्ताव बनाकर जल जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारी से यहां पुल बनाने का मनोरथ किया जाना तय कर्तव्यमान पुरुषों के पुरुषों को जिलाधिकारी विधायक के नाम प्रस्ताव देने का आवागमन प्रस्ताव कर दिया। यहां पर एक लॉन्डर जल प्रवाहित हो रहा है जो आपास पास सभी श्रेष्ठों को जल से संतुष्ट कर दिया। इसके पास एक लॉन्डर जल प्रवाहित हो रहा है जो आपास पास सभी श्रेष्ठों को जल से संतुष्ट कर दिया।

ग्राम से आवागमन पूरी तरह धारा के उपायक कार्यक्रम राज शुक्ल, बलूलाही वारपाल के युवा ग्रामीणों के पुरुषों को जिलाधिकारी विधायक की तरफ से जिलाधिकारी विधायक के नाम प्रस्ताव देने का आवागमन प्रस्ताव कर दिया। यहां पर एक लॉन्डर जल प्रवाहित हो रहा है जो आपास पास सभी श्रेष्ठों को जल से संतुष्ट कर दिया। इसके पास एक लॉन्डर जल प्रवाहित हो रहा है जो आपास पास सभी श्रेष्ठों को जल से संतुष्ट कर दिया।

पेट्रोल पम्प पर हुई लूट की घटना ने तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। कोतवाली के लालगंज कालाकारकर हाइवे पर बीती बृहदीवार की दोपहर तीन नकाबपेश बदमाशों द्वारा पेट्रोल पम्प पर हुई लूट की घटना की जांच जारी की गयी। जिसके पास से अधिक की जांच जारी की गयी।

बुधवार को अपराह्न करीब तीन बजे कोत

सम्पादकीय

फिर बेनकाब हुआ पाक, सार्क देशों की बैठक कैसल, जाने क्या है इसके मायने

सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की शनिवार 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रस्तावित बैठक केंसल हो गई। इस प्रकरण में पाकिस्तान का वह चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया, जिसे तरह-तरह के उपायों से दुनिया से छुपाने की नाकाम कोशिश वह लगातार करता रहा है। साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन यानी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की शनिवार 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रस्तावित बैठक केंसल हो गई। इस प्रकरण में पाकिस्तान का वह चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया, जिसे तरह-तरह के उपायों से दुनिया से छुपाने की नाकाम कोशिश वह लगातार करता रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान को मिल रहे पाकिस्तानी समर्थन में किसी तरह का संदेह किसी को भी नहीं रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान इसके बावजूद दावा करता रहा है कि वह तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा और अफगानिस्तान में अगर उसकी कोई दिलचस्पी है तो यही कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। लेकिन काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन की बैठक का यह पहला मौका आया नहीं कि पाकिस्तान ने इसमें तालिबान की नुमाइंदगी का सवाल उठा दिया।

सभी जानते हैं कि तालिबान की कथित सरकार को अभी किसी भी देश की मान्यता नहीं मिली है। उसके द्वारा घोषित सरकार के घटकों के बीच भी रह-रह कर हिंसा और मारपीट की खबरें आ रही हैं। उस कथित सरकार के कई प्रमुख सदस्य संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में या दूसरे देशों की वॉन्टेड लिस्ट में हैं। ऐसे में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तालिबान को शामिल करने की जिद का भला क्या औचित्य हो सकता है? स्वाभाविक ही अन्य सार्क देश इस आग्रह को विचार करने लायक मानने को भी तैयार नहीं हुए। चूंकि इस पर आपस में कोई सहमति नहीं बन पाई और सार्क में कोई भी फैसला सर्वसम्मति से ही लिया जाता है, इसलिए बैठक को रद्द कर दिया गया। आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान की ऐसी संदिग्ध भूमिका के ही कारण सार्क का मंच निष्क्रिय ही नहीं मरणासन्ध हो गया है।

2016 में इसको 19वां शिखर बॉठक इस्लामाबाद में हानी गाली थी, मगर उरी में अंडियन आर्मी कैप पर हुए आतंकी हमले के चलते इसे रद्द करना पड़ा था। तब से इसका कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। पाकिस्तान के अंडियल रुख का असर इसके सामान्य कामकाज पर भी हुआ है। किसी मसले पर आम सहमति तक पहुंचना करीब-करीब नामुमकिन हो गया है, जिस वजह से एक दौर में संभावनाशील माना जाने वाला यह मंच निरर्थकता की गति को प्राप्त होता जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान-इन आठ दक्षिण एशियाई देशों की सदस्यता वाले इस संगठन से चीन, युरोपीय समुदाय (ईयू), ईरान, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, म्यांमार और अमेरिका ऑब्जर्वर के रूप में जड़े हुए हैं। जाहिर है, दुनिया के 3 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र, 21 फीसदी आबादी और 4.21 फीसदी इकॉनॉमी को कवर करने वाले इस संगठन की इस पूरे क्षेत्र में शांति, सहयोग, और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। ऐसा न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा।

चौटाला की जींद रैली और विपक्षी एकता के यक्ष प्रश्न

राजेद्र शर्मा

इस समर्थन के लिए इसका भरोसा होना भी ज़रूरी है कि संघ-भाजपा के सत्ता से हटाने का दावा करने वाली विपक्षी कतारबंदी, सचमुच आम जनता के हितों की रक्षा करेगी, उन्हें आगे बढ़ाएगी। जनता के मुद्दों पर संघर्ष के पक्ष में विपक्षी की बढ़ती एकता, ऐसा भरोसा दिलाने वाला राजनीतिक-नीतिगत मंच बनाएगी और विपक्षी पार्टियों को उसके प्रति प्रतिबद्ध भी करेगी। ऐसी एकता ही विपक्षी पार्टियों की बढ़ती संख्या को अंथ-कांग्रेसविरोधी की वैचारिक ग्रस्ताता से भी निकालेगी। यह भारत में विपक्षी एकता का सीजन है। विपक्षी एकता के चर्चे हवाओं में है। ऐसे में अचरज की बात नहीं है कि शिक्षक भर्ती घोटले में अपनी सजा पूरी कर, हरियाणा में फिर से अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे औमप्रकाश चौटाला, ऐलान कर गैर-कांग्रेसी, गैर-भाजपा पार्टियों को एकजुट करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। इस अभियान के लिए, उनके लिए चौंधरी देवीलाल के जन्म दिन पर आयोजित रैली से उपयुक्त दृसरा मौका नहीं हो सकता था। अखिरकार, चौंधरी देवीलाल इमर्जेंसी के दौर से सामने आई कांग्रेसविरोधी विपक्षी एकता के प्रमुख स्तंभों में एक रहे थे और इसी विपक्षी एकता के बल पर देश के उप-प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। 25 सितंबर को जोंद में आयोजित रैली के लिए, लगभग तमाम गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा पार्टियों को आमंत्रित किया गया है और चौटाला ने खुद कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया है। बिहार की जदयू-भाजपा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात ने खासतौर पर लोगों का ध्यान खींचा है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आपने आंदोलन के दस महीने पूरे होने पर प्रस्तावित, भारत बंद की तारीख, आगे खिसका कर 27 सितंबर तिता तारा त्रैमास के लाए जाएगी और यही तिता त्रैमास है।

किया जाना, देवीलाल के नाम के महत्व को ओर ही इशारा करता है। बेशक, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि जीड़ रैली में अंततः कौन-कौन से नेता जुटते हैं इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विपक्षी नेताओं के इस जमावड़े से क्या विपक्षी एकता के प्रयासों को क्या कोई वास्तविक गति मिलेगी वास्तव में यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षी नेताओं के इस जमावड़े के जरिए, ओमप्रकाश चौटाला की पहली कोशिश तो देवीलाल के असली उत्तराधिकारी के रूप में अपना दावा मजबूत करने तथा अपने सहारे पार्टी के आईएनएलडी गुट की ताकत बढ़ाने की ही होगी। उनकी कोशिश होगी कि देवीलाल की विरासत की लडाई में, बागी हाकर भाजपा के गुजराल को संयुक्त मार्चा सरकार, भाजपा के नेतृत्व वाले गठजोड़ के वर्चस्व के खिलाफ केंद्रित और कांग्रेस द्वारा समर्थित थीं। यूपीए-1 के दौर में, विपक्षी ध्रुव पर कांग्रेस और अन्य ताकतों के बीच का समीकरण पलट गया, जबकि विरोधी ध्रुव पर एनडीए ही बना रहा। और जहां तक वर्तमान का सवाल है, यह समझने के लिए राजनीति का विशेष ज्ञान होने की जरूरत नहीं है किंतु 2019 के चुनाव में 40 फीसद से ज्यादा वोट जुटाने में समर्थ हुए, मोदी-आरएसएस के नेतृत्व वाले मोर्चे को व्यावहारिक चुनौती, इस मोर्चे के खिलाफ या उससे बाहर पड़े करीब 60 फीसद वोट को कम्पेबेश एक ध्रुव पर इकट्ठा करने में समर्थ विपक्षी एकता से ही दी जा सकती है। वक्त का तकाजा है।

साथ गठजोड़ सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, अपने पोते दुष्ट चौटाला की जेजेपी को, अगर बेदखल नहीं भी किया जा सके तो, इतना कमजोर जरूर कर दिया जाए कि वह खुद, किसी सुलह-समझौते के लिए मजबूर हो जाए। इसी से आईएनएलडी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की उम्मीद कर सकती है। सभी जानते हैं कि करीब दस महीने से जारी किसान आंदोलन के निशाने पर, हरियाणा सरकार के हिस्से के तौर पर दुष्ट चौटाला की पार्टी भी आई है और इसे ओमप्रकाश चौटाला गुरु, देवीलाल की विरासत के अपने दावे को मजबूत करने के लिए, सबसे अनुकूल मौका मान रहा है। इसलिए, जींद रैली में किसान आंदोलन का खूब जौर-शोर से समर्थन किया जाना भी तय है। वैसे भी देवीलाल की छवि तो चौधरी चरणसिंह के बाद, उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता की ही है। अचरज नहीं होगा कि जींद रैली, अन्य अनेक गैर-कंग्रेसी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने के अलावा एक और प्रकाशसिंह बादल और दूसरी ओर नीतीश कुमार को एक मंच पर लाने में कामयाब हो जाए। किसान आंदोलन के दबाव में ही अकाली दल को, सत्ताधारी एनडीए से नाता तोड़ना पड़ा था, जबकि नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों की असहजता किसी से छूपी नहीं है। दोनों अगर जींद रैली में पहुंचते हैं, तो यह एक बड़ी खबर होगी और इससे विपक्षी एकता के प्रयासों में एक नया तत्व जुड़ेगा। असंभव नहीं है कि विपक्षी एकता

दलित शब्द के उपयोग से क्यों रोका जा रहा है ? क्या है दलित का शाब्दिक अर्थ ?

राकेश सैन

दलित शब्द का शाविक अर्थ है- दलन किया हुआ। भारतीय वांगमयी में दलित का अर्थ शंकराचार्य जी ने मधुराष्ट्रकम् में द्वैत से लिया है। उन्होंने 'दलितं मधुरं' कहकर श्रीकृष्ण को सम्बोधित किया, उनके कहने का अर्थ है कि श्रीकृष्ण जी के पांवों ताले दली गई या कुचली गई हर वस्तु मधुर है। पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने घेतावनी दी है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रयोग किए जाने वाले दलित शब्द से गुरेज किया जाए। प्रदेश में हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन के दौरान नए मुख्यमन्त्री चरनजीत सिंह चंडी को लेकर बार-बार दलित जैसे आपत्तिजनक व अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया। आयोग की अध्यक्षा श्रीमती तेजिन्दर कौर ने इसे गम्भीरता से लेते हुए कहा कि देश के संविधान व

ताजन्दर कार ने इस गम्भीरता से लत हुए कहा। एक दश के सावधान के विधान के किसी भी अध्याय में इस शब्द का वर्णन नहीं है, इसीलिए इंटरनेट मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सामान्य बोलचाल की भाषा में अनुसूचित जाति के लिए दलित शब्द का प्रयोग न किया जाए। आयोग की अध्यक्षा ने समर्द्ध दिया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की गवालियर पीठ की तरफ से 15 जनवरी, 2018 को जनहित याचिका 20420 का 2017, डॉ. मोहनलाल माहौर बनाम भारतीय संघ व अन्य के अन्तर्गत निर्देशित किया गया है कि केन्द्र या राज्य सरकार और इसके अधिकारी व कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 'दलित' शब्द का प्रयोग करने से परहेज करें, क्योंकि यह भारत के संविधान या किसी कानून में मौजूद नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ही केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे चुका है कि अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों व वर्गों के लिए 'दलित' की बजाय 'अनुसूचित जाति' शब्द का ही प्रयोग किया जाए। हाल ही में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग 13 सितम्बर, 2021 को प्रदेश की मुख्य सचिव विनी महाजन को लिखें एक पत्र में जाति आधारित नामों वाले गांवों, कस्बों और अन्य स्थानों के नाम बदलने और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से परहेज करने के लिए कह चुका है। इसके अलावा साल 2017 में राज्य सरकार की तरफ से सरकारी कामकाज में हरिजन और गिरिजन शब्द नहीं बरतने का भी निर्देश दिया था।

दलित शब्द का शार्क्कक अर्थ है- दलन किया हुआ। भारतीय वागमय में दलित का अर्थ शंकराचार्य जी ने मधुराष्ट्रकम् में द्वैत से लिया है। उन्होंने 'दलितं मधुरं' कहकर श्रीकृष्ण को सम्बोधित किया, उनके कहने का अर्थ है कि श्रीकृष्ण जी के पांवों तले दली गई या कुचली गई हर वस्तु मधुर है। परन्तु महाराष्ट्र में चले बाबा साहिब भीमराव आँडेकर के आन्दोलन के बाद इस शब्द का प्रयोग जाति सूचक प्रतीकों के लिए किया जाने लगा। हिन्दी में जातिसंघक शब्द के रूप में यह शब्द मराठी से आया बताते हैं जिसका अर्थ किया जाने लगा कि वह व्यक्ति या वर्ग जिसका शोषण-उत्पीड़न हुआ है। रामचन्द्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है- मसला, मर्दित, दबाया, रौन्दा या कुचला, विनष्ट किया हुआ। पिछले छह-सात दशकों में 'दलित' शब्द का अर्थ काफी बदल गया और परी तरह जातिसंघक बन गया है। देश में चलने वाली जातिवादी राजनीति ने तो इसे पूरी तरह विकृत कर दिया है। इस दौरान देश में यह विमर्श भी चला कि दलित शब्द का प्रयोग केवल कुछ जातियों के लिए ही क्यों किया जाए, जबकि दलित तो हर भारतीय है जो कई सदियों तक कभी मस्लिमों तो कभी युरोप के इसाई लुटेरे हमलावरों



उ उनकी सत्ता द्वारा कुछला जाता रहा है। इन विदेशी शक्तियों की सत्ता के चलते करोड़ों भारतीयों की हत्या, जबरन धर्मान्तरण, महिलाओं र अत्याचार, अकूट धन सम्पदा की लूट हुई। और सबसे अधिक भयावह त्रासदी तो 1947 के देश विभाजन के समय के समय झेलनी पड़ी ज युगों से अखण्ड चले आ रहे एक राष्ट्र को दो हिस्सों में बांट दिया गया। लगभग 12 सदियों तक निरन्तर लूटपाट और अत्याचारों ने हर भारतीय को मसला और दलित बना दिया। फिर प्रश्न पैदा हुआ कि इन पीड़ित भारतीयों के भीतर भी जो पिछड़े हुए लोग या वर्ग हैं उनको क्या नाम दिया जाए? तो इनका 'वंचित वर्ग' का नामकरण किया गया। वंचित वर्ग अर्थात् वह वर्ग जो आज केवल संसाधनों से वंचित है, अन्यथा उनके और समाज के बाकी अंगों में किसी स्तर का कोई अन्तर नहीं है। इन वर्गों का यह वंचित वर्ग नाम अलगाव को दूर करने वाला परन्तु दलित नामकरण अपमानजनक होने के साथ-साथ समाज में विभेद पैदा कर वाला है। देश में अलगाववाद का विमर्श स्थापित करने में लगी शक्तियों दलित शब्द का खूब दोहन किया और वंचित वर्ग में अलगाव की भावन पैदा करने के लिए इसका खूब दुरुपयोग हुआ है। नक्सली, जिहादी

चर्चा प्रयोजित संगठनों द्वारा प्रचारित दलितवाद, अम्बेडकरवाद, द्रविड़-आर्यवाद, मूलनिवासीवाद आदि इसके उदाहरण हैं कि किस तरह इस दलित शब्द को तलवार की तरह प्रयोग किया जाता रहा है। सुविधाजनक होने के चलते यह शब्द जातिवादी राजनीतिक विमर्श का भी हथियार बना, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या फिर दक्षिण के द्रविड़ अस्प्लिन की राजनीति करने वाले दल, सभी ने दलित शब्द की आड़ में खूब सियासी मालपूरे सेंके हैं। केवल इतना ही नहीं देश के छछ धर्मनिरपेक्ष दल भी इस खेल में किसी से पीछे नहीं रहे, चाहे ऐसा करते हुए देश व समाज को कितना भी नुकसान पहुंचा हो। राजनीति में यह विमर्श इतना झङ्गारूप ले चुका है कि मीडिया विश्लेषणों में भी इसका प्रचलन आम बात हो गयी है। हर चुनाव का विश्लेषण करते हुए लगभग हर मीडिया हमें बताता है कि अमुक इलाके में कितने हिन्दू मत हैं, कितने दलित और कितने अत्यसंख्यक। इन विश्लेषणों में दलित को हिन्दुत्व की मुख्यधारा से अलग करके दिखाया जाता है। अगर दलित शब्द को पूरी तरह प्रतिबिधित करके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति शब्द अनिवार्य कर दिया जाता है तो इस अलगावादी विमर्श की धार अवश्य कुन्द होगी। देश अपनी स्वतन्त्रता की 75वीं जयन्ती मनाने की तैयारी कर रहा है और अमृत महोत्सवों की धूम है। यह बौद्धिक नवाचार व सुधारों की बेला है। यही उचित समय है कि समाज में प्रचलित भ्रामक, गलत, अपमानजनक और बिखराव पैदा करने वाली शब्दावलियों पर पूर्ण विराम लगाया जाए। हरियाणा सरकार ने हाल ही में गुरु गोरखनाथ सम्प्रदाय की भावनाओं को ध्यान में रख कर गोरखधर्मा शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कितने दशकों से गुरु गोरखनाथ जी के नाम से एक अपमानजनक विशेषण जोड़ कर उनको अपमानित किया जाता रहा है यह दुर्भाग्य की बात है। उसी तरह दलित शब्द से भारतीय समाज के एक वर्ग का भी अपमान हो रहा है और उनमें अलगाव की भावना पैदा हो रही है। उचित समय है कि दलित शब्द पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाया जाए और समाज में चल रहे झूठे विमर्श को रोका जाए।

सप्राट मिहर भोज का इतिहास

यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए बना सिरदर्द

संजीव सिंह

की पाठ्यपुस्तकें उन्हें गुर्जर-प्रतिहार वंश से संबंधित बताती हैं। राजपूत समुदाय इससे नाराज है क्योंकि यह साक्षित करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य और सबूत हैं जो बताते हैं कि मिहिर भोज शाही प्रतिहार राजपूत वंश से संबंधित थे। इतिहास के उस दौर में 'गुर्जर' शब्द हमेशा एक भूभाग (राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों) के लिये प्रयोग किया जाता था ना कि किसी जाति विशेष के लिये। राजपूतों को कॉलेज में स्थापित मूर्ति से कोई समस्या नहीं है क्योंकि सप्राट मिहिर भोज एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं; उनका गुस्सा विशेष रूप से प्रतिहार राजपूत राजा को पड़िका में गलती से 'गुर्जर' कहे जाने पर है। वे इसे अपने इतिहास के विनियोग के रूप में देखते हैं। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ, जो राजपूत युवाओं में भी बहुत लोकप्रिय हैं, ने सप्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया तिने गर्भी के सामने चिन्हित किया था। सिंहस्त्रे कहा जाता है कि यही

ज़ान्ह गुजर के रूप में चारत बिकाया गया है। पछले कुछ दशकों से यहा माना जाता है कि राजपूत समुदाय अंदरूनी कलह के कारण विभाजित रहता है। परंतु इस घटना ने दिखा दिया का आज का राजपूत युवा अपने अतीत को छोड़ कर एकजूट होने को तैयार है। उनकी सामूहिक ताकत जब दिखी जब युवाओं ने ट्रिविटर जैसे सोशल मीडिया प्लॉफॉर्म पर 17 सितंबर को, 19 सितंबर को और 21 सितंबर को जैसे हैशटैग टॉप ट्रैन्स में शामिल कर दिया। इन तीनों हैशटैग पर क्रमशः 3 लाख से अधिक ट्रीविट्स किये गये। ऑनलाइन आंदोलन की सुगबुगाहट ज़मीन पर भी दिखी जब कई राजपूत संगठनों ने दादरी में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। कुछ समाचार एजेंसियों से पता चलता है कि 22 सितंबर को होने वाले आयोजन के 30 किमी के दायरे में आने वाले अधिकांश राजपूत गांवों में पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी थी। यह भाजपा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, खासकर चुनावी मौसम के दौरान, जब तिपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधने के लिये भावनात्मक महों की तलाश कर रहे हैं।

विभिन्न अनुसारों के अनुसार, पश्चिमी यूपी में गूजर लगभग 23.5 मतदाता हैं और वे नोएडा और अविभाजित मुजफ्फरनगर जिलों में 6-8 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। राज्य में राजपूत वोट लगभग 10-12.5 है और समाज रूप से फैला हुआ है। राजपूत बड़े मतदान पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं, यही वजह है कि उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीटें मिलती हैं। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि अधिकांश समुदाय राजनीतिक सत्ता में बड़ा हिस्सा पाने के लिये अपनी संख्या बढ़-चढ़ कर बताते हैं। किंतु अगर हम भारत में हुई जाति आधारित अंतिम जनगणना रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो वास्तविक संख्या बनाम दावा की गई संख्या साफ हो जाती है। 1931 की जाति जनगणना के अनुसार, तत्कालीन युनाइटेड प्रॉविंसेस (अब उत्तर प्रदेश) में गूजरों की जनसंख्या 0.73 और राजपूतों की जनसंख्या 7.23 थी। भले ही योगी आदित्यनाथ राज्य भर में एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन भाजपा का चुनावी गणित अब भी बिगड़ सकता है। गाजियाबाद और सहारनपुर के बीच पश्चिमी यूपी की लगभग 120 सीटों पर राजपूत वोट भाजपा की धार को कुंध सकता है। यह योगी आदित्यनाथ के लिए विडंबना होगी कि जिन्हें केवल एक राजपूत नेता के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और अक्सर मुख्यधारा की मीडिया उनको राजपूतों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिये उनकी आलोचना करती है, उन्हें उसी समुदाय के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। शायद इस पहलू पर मीडिया कवरेज की कमी का एकमात्र कारण यह है कि यह मुद्दा उनके लोकप्रिय नैरेटिव में फिट नहीं बैठता है।

चांदनी चौक की रैनक हैं ये

ऐसी कौन सी जगह है, जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स ना हो? इंडिया गेट के पास आइसक्रीम बेचती रहड़ियां, यूपीएससी के पीछे की चाट, यहाँ तक एयरपोर्ट पर भी वेंडर्स होते हैं। जहाँ आम आदमी हैं, वहाँ उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वेंडर हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस से चांदनी चौक - जो कि एक नो-वेंडिंग जोन है - में वेंडर्स की उपस्थिति का कारण पूछा। कोर्ट जवाब चाहता है कि आखिर चांदनी चौक से स्ट्रीट वेंडर्स को पूरी तरह से क्यों हटाया नहीं गया। स्ट्रीट वेंडर कानून 2014 के अनुसार 'नो-वेंडिंग इलाका' नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण, टाउन वेंडिंग समिति की सलाह से ही तय कर सकता है। मगर हाई कोर्ट का तर्क है कि चांदनी चौक 'पहले से' ही नो-वेंडिंग इलाका घोषित है। पहले से एक समस्या है - जिसका समाधान ये नया कानून यानि कि 2014 का कानून है। चूँकि 'पहले से' कोई विधायिका द्वारा पास किया कानून नहीं था, सिर्फ कागजी नीतियों के आधार पर नगर निगम नो-वेंडिंग जोन बनाती गयी। कुछ केसों में, अदालतों ने नो-वेंडिंग जोन की हरी झंडी दी। लेकिन हमारी संवैधानिक व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है - कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास नहीं। इसी सिद्धांत के अनुरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सितम्बर 2013 को 'महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन' केस में एक आदेश दिया - कि पुराने जो भी, जितने निर्देश और आदेश हैं, वो सिर्फ नया कानून आने तक ही वैध होंगे। अब जब संसद द्वारा पास किया कानून लागू है, तो पुराने सर्वे और नो-वेंडिंग जोन की मान्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। 2014 का कानून भी साफ-साफ कहता है कि जब तक कानून के अनुसार सर्वे नहीं हो जाता, तब तक कोई वेंडर को उसकी जगह से हटाया न जाए। कानून की पूरी तरह धज्जियाँ उड़ाते हुए कई शहरों में वेंडर्स को उनकी जगह से बेदखल किया गया। नए कानून के अनुसार, कोई नेचुरल मार्किट, जहाँ वेंडर्स अपना बाजार लगाते रहे हो, वो कभी नो-वेंडिंग इलाका नहीं हो सकता। भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम के कारण कभी वेंडर्स को हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि भीड़-भाड़ और जाम लगाने के कारण तो पैदल चालक, गाड़ियों, रिक्शों, और दुकानदार की वजह से भी होता है या हो सकता है, ऐसे में केवल स्ट्रीट वेंडर ही जिम्मेदार क्यों? साफ-सफाई रखना नगर निगम का काम है, और गंदी फैलाने पर निगम के पास जुर्माना लगाने का अधिकार भी है, इसलिए गंदी की वजह से भी वेंडरों को हटाया नहीं जा सकता। नया कानून तो यहाँ तक कहता है कि सर्वे से पहले नो-वेंडिंग जोन तय नहीं किया जा सकता। जहाँ पथ

